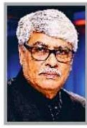


चिंतन
कब तक युद्ध की कीमत
चुकाएगी अर्थव्यवस्था

युद्ध को ही नहीं, तबवर्षा हमेशा मिखाइल, टैंक और सैनिकों को होता है। लेकिन उसका सबसे लंबा और गहरी भार अर्थव्यवस्था पर पड़ती है। रूस-यूक्रेन युद्ध में अब ओलिम्पिक प्रतिस्पर्धा और ऊर्जा बाजार में भी है। दूसरी ओर अमेरिका-इजरायल और ईरान के संघर्ष ने जूनिया को खिंच दिया है कि कौसी एक बर में युद्ध को आगे प्रभावित पर उसकी लक्ष्य है, नए जहाजों, मर्हाबां और वैश्व व्यापार तक पहुंच सकता है। इसके ने महीने में हमेशा जवाबदायित्व में जहाजों की अवाजोबां वही तरह प्रभावित होना है। जबकि एक हिस्सा युद्ध में करीब पांच सौ हज़ारों के होते हैं एलमेट्ज़ी जहाजों के हिस्से में हैं। अंतरराष्ट्रीय युद्ध को नये भी पोतबां है। युद्ध के कारण तक बाजार पर युद्ध इतना वैश्व अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम बना सकता है। इससे बीबी यूएफ के क्रिचो हार में भारतीय उद्योगों को बर्षाव्यवस्था स्थिति मिलत की संकेत। इस्मेल में दो लोगों को मौत और 13 अक्षरवांयों ने उकेरते दो पाकवर्ष होते की खबर है। प्लांट की ऊर्जा व्यवस्था और वातावरण से जुड़े अमर हिस्से की उम्काना पैदा करे और उपकरण का कुछ काम होना। हर हिस्से एक फेक्टरी पर इस्मेल नहीं है, बल्कि उस आर्थिक बाजार पर इस्मेल है। इस्मेल का क्रिचो देश के उपानतन क्षमता खंडी होती है। स्ट्रुट को आनुवंशिक उपकरणों की रीस कहा जाता है। सड़कें बनाते हैं, पुल खड़े करते हैं, तेलवे का विस्तार करते हैं, जहाज बनाते हैं या इस उपकरण तैयार करते हैं। हर जगह स्ट्रुट की जकड़त है। इस्मेल हिस्से बड़े स्ट्रुट संघर्ष की उपानत क्षमता प्रमाणीत होती है। केवल कर्मचारी के उम्काना तक सीमित नहीं होता। इसके साथ कच्चे मानव शक्ति, परिवहन, रक्षण, निष्ठा और खान्दा दूसरी औद्योगिक इकायों की परिवर्धित प्रमाणीत होती है। युद्ध जग बरखावत तक पहुंचता है तो उम्काना अधिक कर्मचारी कड़ गुना खड़े होता है। संघर्ष फिरे की बाव है कि एक आर्थिक बांच अब युद्ध को एनीति का हिस्सा बनता जा रहा है। आसंमेल मिलत के हम संघर्ष को 2022 में भी फिरीना बनाया था। यानी वार साल बाद भी औद्योगिक प्रतिस्पर्धा सुखित नहीं है। एक मिखाइल कुछ बाजार में उस उपानत क्षमता को फुलनफुल एकपुछ सकता है, तैयार करके में वैं और अबसे खरवें करता है। इसके बाद पुनर्निर्माण का बीसा भी उनी अर्थव्यवस्था को उपानत पहुंचता है, जो पहले ही युद्ध से कमजोर हो चुकी होती है। भारतीय कर्मचारी के लिए भी एक एह बड़े घटना होती है। वैश्विक निरक्षर के दर में कर्मचारी नए बाजारों और संसाधनों की मदद में दुनिया के अलग-अलग हिस्से में पहुंच रहा है, लेकिन अब निरक्षर का फैसला करके बाजार और मनुष्य के अंतर पर नहीं हो सकता। धनवांनिक निरक्षर, युद्ध का जोखिम, युद्ध का जोखिम, समुद्री मार्ग और आनुवंशिक युद्ध को मजबूती भी निरक्षर के ऊर्जी मनुष्य होते चाहिए। विरंडा बना है कि युद्ध लड़ने वाला देश सैन्य जोर का दया कर सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में असमेल पैज की संकष्ट बड़ी समीक्षा चुकाता है। अगर मनुष्य के लिए युद्ध का मारल नक्शे पर बदलती सीमा नहीं, बल्कि हमेशा इरान, महीने जोरों, अमेरिगल निरक्षर और अनिश्चित फिरीना होता है। युद्ध कुछ पैर में अर्थव्यवस्था की दरवाकी को मेहनत को मिल सकता है। आर्थिक चक्र तक अर्थव्यवस्था को को कानत चुकाता होगा। इस्मेल निरक्षर है कि सभी सामान्य कुटनीती, संवाह और वार्ता में फिरेले अपनो। स्ट्रुट अर्थव्यवस्था सुखित रहा है।

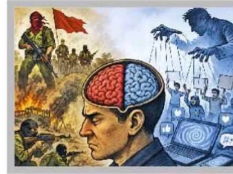



नई बहस
 ओमकार चौधरी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से 'दिमागी नक्सल' शब्द का इस्तेमाल कर देश की आंतरिक सुरक्षा की बदलती तस्वीर पर गंभीर बहस छेड़ दी है। बंदूक उठाने वाला नक्सलवाद कमाजोर पड़ा है, लेकिन उससे जुड़ी हिंसा और अराजक मानसिकता के नए रूप सामने आने की आशंका जताई गई है। ऐसे में आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, 'अर्बन नक्सल' और 'दिमागी नक्सल' के बीच अंतर समझना जरूरी हो जाते हैं। खासकर डिजिटल दौर में विचार, दुष्प्रचार और सोशल मीडिया के जरिए असंतोष को हिंसा की ओर मोड़ने की चुनौती सुरक्षा एजेंसियों के सामने नया सवाल खड़ा कर रही है।

दिमागी ਨਕਸਲ ਕੀਓਂ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਚੁਨੌਤੀ?

होगी, लेकिन उसकी परिचालन क्षमता को कई स्तरों पर गंभीर चोट पहुंचे। नरमसलवाली को कहानी इससे अलग है। 1967 में नरमसलवाली से निकला माओवादी आंदोलन धीरे-धीरे सरासरी विद्रोह में परिवर्तित हुआ और छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगना, बिहार तथा पश्चिम बंगाल के हिस्सों में इसका प्रसार फैलता था। एक संयोग के तरीके से अधिक जितने किसी न किसी रूप में नरमसली हिंसा से प्रभावित माने जाते थे जंगलों के भीतर नरमसली संगठन अपनी समानता स्थापना चलाते थे। वे पुलिस कमरियों और सुखाब्जियों को हत्या करते थे, सरकारों भवनों को उड़ाते



थे, मुद्रक और लेखक को तो निराना बनाते थे और स्थानीय आबादी से रजत चूस सुरूते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2022 के संकेतचित्र में कहा कि नक्सलवाद और माओवाद ने हज़ारों युवाओं का परिचय बलिदान और चार दशकों तक देश के बड़े हिस्से तथा विश्व के अखादी को बुंदुक के भय में डाला। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य नागरिकों के श्रम करों से 7,50,00 से अधिक पुलिस और सुरक्षा कर्मीयों ने जलानंद विमान, लखनौ में प्रथम-मंजरी को सुरक्षा वित्तित कर लिया है। हॉलिवुड-नक्सली पीजुजिन ने गुगल, लैकन-नक्सली-मार्क्सवादी को भी पीजुजिन है। ऐसे तब नक्सली नश्वर हैं, हिंस और अराजकता के तारों की छवि है और सामंज को गलत दिशा में ले जाने के लिए अलग-अलग तंत्र अपना रहे हैं। यही सब संघर्ष है जिसमें निराला नक्सल श्रम्य सामने आया। सामान्यता के संस्था प्रदेमाल उन लोगों के लिए किम्व जितना ताता को थ्यंय अंगुली में बुंदक लेकर नश्वर है, लोका मोआडोही हिंस अथवा उल्लेख वैचारिक आभार के प्रति सहजगीपुन खलते हैं, उसे वैचारिक, वैदिक या यमराजक समर्थन देते हैं। अथवा यथार्थवादी-सिरोमिणी अंकन अंगुली को वैध इहदने का थ्यास करते हैं। हालांकि “अन नक्सली” को यथंय वैध कर्नो अंगुली नहीं है और यथंय के राजनीतिक प्रदेमाल को लेकर लक्ष्य ले समर्थन से शिवार रहे हैं। इंदोअरिए अल प्रदेमाल श्रम्य

केवल सन्तानों के प्रति अथवा अंगणों का प्रचन नहीं रहे यह। सन्तान का क्षेत्र भी यन्त्र कुशलेन न चक्रे है। सामाजिक माध्यम, कृषि-पट्टा की ओटना, कृषि में संशोधन से श्रेष्ठ सामान्य, धूप-बिजली, झूटी सन्तान और संशोधन यन्त्रा कुल दृष्टि में लाखों लोगों को प्राणित कर सकने के लिए। स्थानीय विधायकों के राष्ट्रीय स्तर पर जाने जा सकते हैं। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, बेरोजगारी, परीक्षा किन्तु, छात्र अथवा अंगणों में अन्तर्गत विद्यार्थी के संस्कार देश की ओर अस्तित्व में आकर सन्तानों। शिक्षकों से है। शिक्षक द्वारा में मातृणा पहलू की तुलना में अधिक आसान हो गया है। यहाँ तक क्षेत्र है जो 'दिगम्बर नरकल' को अन्तर्गतों को केवल प्राणों में आजीवक के रूप से नहीं ज्ञात जा सकता। यह दर्शना अथवा एषिय मानसिकता को है जो लोकतांत्रिक मानसिकता को हलसकर आराजकता में बदलना चाहती है, समाज के विभिन्न वर्गों को लगातार एह-उत्तर अथवा रण के विरुद्ध यन्त्रता को है और संशोधन रण के बजाय अन्तर्गतों को परितंत्रित का माध्यम मानती है, तो यह वास्तव में आधुनिक आधुनिक सन्तानों को गंभीर चेष्टी है।

पूरा नरसलदण्ड को पहचानने अथवा श्रुतानुसार आगम-
या ज्ञान में परिवर्तन करने से, निमित्त साधन के रूप में
कर्ममंडप से, प्रशिक्षण शिविर से और प्रभात शिव से
आकाशवादी को पहचान भी उत्पन्न होता है, शिवध्वज
विशेष नेटवर्क अथवा हिंसक कार्यवाही से जो जा सकते
हैं। लेकिन विचार और धृष्टता के क्षेत्र में काम करने
वाले नेटवर्क को पहचानना कठिन है। महा अश्विन और
विचार, असाधकता और उन्माद, आदिशन और
आराधना के बीच बहुत गहन अंतर होता है। इसलिए
हमें सम्पूर्ण दृष्टि चुनौती है। एक तरफ उसे उन्माद
नेटवर्क पर निगरानी रखनी होगी जो हिंसा
अलगवादावा, आकाशवादी अथवा मोहोदय विद्रोह के
लिए वैचारिक और प्रशासनिक वातावरण तैयार करती है।
दूसरी तरफ उसे वह सुनिश्चित करने की भी सक्ती है
आलोचना करने का एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया, श्रुत, लोकक
मुक्तिजीवी, किसान नेटवर्क या राजनीतिक कार्यकारी केवल
असहमति के कारण संदेह से घेरने में न आ जाए। भारत में
आकाशवादी के विवेक बड़े लाड़ा लड़ते हैं। नरसली शिविरों
को भी धोखा है। अलगवादावा नेटवर्क को भी पेशे
चुनौती मिली है। लेकिन सहिष्णुता का यह है हिंसक
विचारवादावा केवल संगठन सम्पन्न होतों से खयम नहीं
होती। ये सम्पन्न प्रवर्गक हैं, नग मुक्त तलाशीय हैं, न
पाप अनगती हैं और नई पीढ़ी में प्रवेश करने का प्रयत्न
करती हैं।

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन
एस एन वर्मा



विदेशी निवेश से ही पूरा होगा नेट-जीरो उत्सर्जन का सपना

गला ग्लामोस में आयोजित 26वें जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नुगेनू दे बात व चीन की वी क्वे बय 2070 तक कार्बन-न्यूट्रल बन आया। लेकिन इस लक्ष्य को साक्ष्यित करने आसान नहीं है। इसके लिए पता को बय 2070 तक लक्ष्य 22.7 डिग्रियाम्मी डॉलर, यानी ओलरत कमी 500 अडॉर प्रिस्तार निशर्ष को अवश्यतक होनी। इसमें लाना 6.5 डिग्रियाम्मी डॉलर का निश्चित उपलब्ध अडमनित है, जिसकी पूंजी के लिए कविशो नरेंद्र जैसी पहली ओ। मोर हाइड्रोजन, बेटी डोर को कमी करके केयर जैसी पहली ओ तदनकीको के विकास के लिए विरोध तदनकी सहयोग और वैश्व पूंजी को भी आवश्यक हो। फिलसल सम्मेलन में किग ग्राफ देर अनुसर भारत बय 2030 तक गैर-जोयाय अडमन को 500 गीगावट तक पहुँचने को दिशान में आया बहर लाते देर में 30 जून 2026 तक गैर-जोयाय अडमन खेती व आयात कर 297.36 गीगावट विद्युत उपलब्ध बनाया स्थिति हो चुकी है। इसमें 288.58 गीगावट 2015-19 की औसत पर 8.78 गीगावट परमाणु अडमन क्षमता स्थिति है। बय 2015-19 में गरीब स्तर पर निशर्षित जलविद्युत (एनपीडी) के माध्यम में उत्पन्न विद्युत उपलब्ध आयात लेकर निर्यात गन था। इसमें 2030 तक जीओपीडी प्रिस्तार औद्योगिक में 33-35 प्रिस्तार की कमी और हिन्दुस्तान संसंधी पर आयातित विद्युत ऊर्जा को स्थिति बनाते में 40 प्रतिशत लक्ष्यसिरी का लक्ष्य रखा गन था। नये जीओ को आगे आंध्र खर देर इसका सोना मालत है। अडमन के प्रोजेक्ट जून वाली गीगावट परसे और ओरने डेने वल्ले अशरोणी को बड़ी संसुल्ल उपलब्ध कराने देर। इस इस्को दिशान में काम शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र को बेला गन इसका उदरगण है। बड़े कार्बन उत्सर्जकों को कमी के लिए बड़े स्तर लहान प्रचणवासी करत उद्योग गन गन व गिवाशरो अभिषेक के लहान 90 इन्डर से अधिक पेर लाना पए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को अशरोणीत करने और वायु गुणवत्ता सुधार में मदद करेगा।। सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए लघोयारों और विद्युत समारोहों जैसे अडमन पर भी घोषणा अभिषेक चलाए पए। स्वच्छ खाना पकाने को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक तकदी में चरने वाली चूल्हों को जगह लाना पए और सौर ऊर्जा आधारित तकदी अपनाना पए। वधिमन में भारत और सूर्यमण्डल के उन देशों में शामिल हो कर कार्बन नोटिड है। यानी निवतन कार्बन उत्सर्जकों को है, उससे अधिक मात्रा में कार्बन उत्सर्जकों को है। नोने देशों को अपनी कम जनसंख्या, सीमित औद्योगिक गतिविधियाँ और बड़े क्षेत्र को बना मिश्रित हो लाना, उत्पन्न उत्सर्जकों से बीच विकाससिरी देर भी उत्सर्जन कम करने में अपना योगदान दे रहे हैं। दुनिया के बड़े कार्बन उत्सर्जकों में शामिल भारत ने जलबल्य स्तर 19 पियरी के लिए अंतरराष्ट्रीय समूह में महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय कर लिए हैं। हालाँकि, अन्य बड़े प्रदूषकों को लाना में भारत का प्रिष्ठ यही उत्सर्जन कम करने है। दुनिया की करीब 17 प्रतिशत आयात कर रहे हैं, जबकि वैश्व उत्सर्जन में औद्योगिक हिसाबती 19 प्रतिशत से भी कम है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए पक्ष सूत्रों पर निशर्षित 'चमत्कार' को घोषणा की। इसके तहत बय 2030 तक गैर-जोयाय अडमन क्षमता को 500 गीगावट तक पहुँचाना, ऊर्जा उत्सर्जकों को बड़ा हिस्सा नवीकरणीय स्रोतों से पए करना, एक अडमन ऊर्जा उत्सर्जन को कम करना और कार्बन उत्सर्जन को निशर्षित में 45 प्रतिशत तक कमी लाना शामिल है। इस लक्ष्य के लिए पक्ष भारत 2070 तक नोडो की दिशान में आयातित रखा है। भारत के अडमन पर बड़े चुनौती कजाइद परफैर यानी जलबल्य परिवर्तन से निपटने के लिए आवश्यक विद्युत जनता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अडमन से जलबल्य विद्युत उद्यम्यता करने को मांग की है। निती आयोग को 'नये जीओ' रिपोर्ट के अनुसार, भारत को 2070 तक इस लक्ष्य को साक्ष्यित करने के लिए पक्ष 22.7 डिग्रियाम्मी अडमन की उदरगण के लिए को जरूरत होगी। बिना बय 2014 से 2026 तक उदर के नवीकरणीय अडमन क्षमता में लगभग 45 अडमन उदर का प्रचण्य प्रिस्तार निशर्ष आया है। आधिकारिक बय 2070 तक उत्सर्जन के बिना इस दिशान में तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होगा। विकसित देशों को तदनकी विकास और जलवायु विन में नुगेनू करतक लाना पए। भारत की अडमन ऊर्जा में बलवत्त के साथ गनगीको जी जलसिरी लाने में परिवर्तन लाने की सीमा रणनीति, प्णयत निशर्ष और वैश्व सहयोग के साथ भारत बय 2070 के लिए सौर लक्ष्य को हासिल करने के दिशान में आगे बढ़ सकता है।



संकलित
दर्शन



संकलित
प्रेरणा

The cartoon shows a snake on the left with a speech bubble that says: "अरे चाची, नागपंचमी पर नया स्टार्टअप शुरू किया है... नेता लोग अपने विरोधियों पर भाषण लिखने की स्याही भी मिलाने को मुझ से ही तो ज़रूर ले जाते हैं..." (Auntie, I've started a new startup on Nag Panchami... Leaders buy ink for writing speeches against their opponents from me, so they must be coming to me for it...). On the right is a shop named "विषवास" (Vishwas) with a sign that says "शुद्ध जहर" (Pure Poison). The shop has shelves of bottles and a snake logo. A small signature "Sanku" is at the bottom left.

करंट अफेयर

होर्मुज पर ईरान-ओमान मिलकर वसूलेंगे टैक्स!

अमेरिका और अंग्रेज़गण द्वारा मिलकर ईरान पर हमला किए जाने के बाद विश्वभर परीया की जगजगती तैरने लगे सच यह है कि, कौमी समी के लिए खुश नरने जलत होमूँ देरने अजक कलत कुल ही देसी के हलर बाए है। अइ दरमामे परने अरबक अरब पर्वतदन होमूँ जे के नुनी कितरने पर खलत नराने और ओमन में इरान समुंद्री रस्ते को लेबरक एरिया समुंद्री तालिका है। हालाँकि, ईरान, ओमन के सारा जग्री मुदत के बाद लतातर इरान बलत पर अउर देहा है इरान हलर होमूँ जे परीस लामने बाए है। हलर देसे परीस नदी बंदीक सुरक्षा के लिए दिरा जाने वाला 'सर्विंस देवस' करन देसी है। अउर नउने देरने जहज्जी कौ और अंबिक सुमिया देरने और तलकर से बलरने के लिए ईरान और अउर समुंदर पर शिपिंग लाना के मिगिण होमूँ। ईराना उदरय जगज्जी के बीदा की कलर को रोवना हलर है। दोरने दिसा के सलता जग हलर इरान समुंदरी को मुल लखर मीरने से उलखे मुसलमन देरने के शिवाक को शत करन और रलतल करन लखलई नउने को देवता से शुकर करन है। इरान मसले पर अमी दोनी देस काम करत हलर है। तलकनीनी सीक हलरने के बाद दिर पर एक आधिकारिक दस्ताजि कलर किए गइया जाले।



केदारेश्वरनाथ मंदिर में बिस्कुट सब्जियों से सजता है शिवलिंग

सासन के पवित्र भवन में देशभर के विद्यार्थी मंदिर में मोलनेवाला का कुल्लो और बेलसपन से विशेष श्रद्धा के साथ बैठते हैं, लेकिन शराबखंड के बोकलरों का एक शिष्ट श्रद्धा अन्वी आंखों पर लपेटे हुए तो ऐसा खास नहीं है।

कैप्टन २ प्रदीप श्री, श्री केन्द्रेवर धाम मनुष्यजन्तु में भावाभिप्राय का श्रद्धा कुल्लो के साथ जागृत, भिन्नी, भगवान्, टावर, हरी कलश, छात्र और यहां तक कि विद्यार्थी से भी किचन जात है। पूजा के बाद इन सामग्रीयों को श्रद्धार्थ के बीच शराब के साथ में बाद दिख जात है। मंदिर के पूजारी निशिका कुमार शर्मा ने बताया कि केन्द्रेवर धाम मनुष्यजन्तु के पवित्र स्थानों पर श्रद्धा के पवित्र धरानों का काम के ध्यान में रखा जात गया है। पहले यहां एक छोटा मंदिर था, लेकिन कहीं डेढ़ घंटे पहले ही गुरु शरण दिया गया और मंदिर का निर्माण अन्वी के करगरी से किया। मंदिर परिसर में मा भवति शां-धम्म, पञ्चमूर्ति द्धुमन शिखर और श्री-देवताओं की प्रमिया श्रद्धा है। पूजारी के अनुसार, जो श्रद्धार्थी कुल्लो शराबका शराबखंड से केन्द्रेवर धाम नहीं आ जा पाते, उन्हें तो मंदिर आस्था का समूह केन्द्र बन गया है। मंदिर की नगदत और धर्मिक वातवरण श्रद्धार्थों को केन्द्रेवर धाम जैसा भावपूर्ण अनुभव करता है।

आज की पाती

आवारा कुत्तों की समस्या

का समाधान जरूरी

विपत्ति हैतरनी और चकित बनकर वाली बात है कि देश के स्वीच-प्लायरों को देश की एक छोटी सी समस्या पर भी ब्रह्मा देव हो जाती है। यह समस्या देश में अमरता को तो अमरमान को हमने वाली है। हाहा ही है खुशमोर्त ने देश में आयात को तो हारा लोको को कटवरी ने से पराजित ने है, और इसका रिशवात से हमने वाली लोको की है पराजित ने है। जल्द ही देश पर गीतवरी पर इसका दोष को हित नहीं, बल्कि विपत्ति को हितवरी। गीतवरी ही दुस्तर को हितवरी के हितवरी समर्थन दिखाता है और प्रसारण को जगने की वीक्षित करता है, लेकिन गीतवरी व प्रसारण है।

गीतवरी नहीं दिखा। गीतवरी की बीमारी जलनेवरी ही बन सखती है। व सरंजिफ समूह समाज को हितवरी ठोस समाधान लतवरी लतवरी।

- विपत्ति कुमार, गीतवरी

ऑफ बीट

✕ ८३



लोकसेवक बड़ी भूमिका निभाएँ



लोकल को ग्लोबल बनाएं



મુમિ નીતિ લાણ્ગે



अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय
टिकराघाटा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फ़ैक्स :
0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से
hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।



श्री राम शरा
shriramshraw
@nda.jagra
n.com

पिछले कुछ दशकों से अमेरिका भारतीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा और करियर की सुविधाओं को देने का सबसे परसिद्ध गंतव्य रहा है, पर हाहा में जारी हुई दो प्रमुख रिपोर्ट ने न केवल भारतीय छात्रों, बल्कि पूरे विश्व जगत में एक चिंता की लहर पैदा कर दी है। अमेरिका की कठोर वीजा नीतियाँ और अनिश्चित प्रशासनिक वातावरण भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बनकर उभर रहे हैं। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत करियर के लिए, बल्कि अमेरिकी अव्यवस्था और नवाचार के भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। वीजा नीतियों की जटिलता में समझे: 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरन स्टूडेंट एडवॉकेट्स' एंशुरेशन आफ इंटरनेशनल एजुकेशन' और 'सेंटर फॉर इमिग्रेशन स्टडीज' (सीआईएस) की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट है कि अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में अंतरराष्ट्रीय छात्रों की संख्या में गिरावट के पीछे एक स्पष्ट कारण है-वीजा निर्णयों का सख्त होना। 2026 के फाल सेमेस्टर तक लगभग 1.1 लाख कम अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पंजीकरण करने का अनुमान है। जहाँ 2025-26 के शैक्षणिक सत्र में 11.69 लाख अंतरराष्ट्रीय छात्रों का अनुमान था, वहीं यह संख्या गिरकर 10.57 लाख पर आ गई है। इस गिरावट में भारतीय छात्रों पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। अंकड़ों के अनुसार, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में 3.63 लाख भारतीय छात्रों ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया था, जो किसी भी देश से आने वाले छात्रों में सबसे अधिक है, लेकिन यह संख्या 2025 के बीच भारतीय छात्रों को जारी किए गए एफ-1 वीजा की संख्या में 60 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। 2024 के 58,694 वीजा के मुकामले 2025 में यह आंकड़ा घटकर मात्र 22,149 रह गया है। यह स्पष्ट संकेत है कि अमेरिकी की नई नीतियाँ प्रवेश के मेधावी युवाओं के लिए प्रवेश को खारिज कर रही हैं। अमेरिकी प्रशासन द्वारा वीजा प्रक्रिया में छात्रों की तुलना में अन्य आवेजनों, जैसे कि फुलटा वलेंट कर डिस्क धारकों को प्राथमिकता देना अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक झटका रहा है। यह बदलाव शैक्षणिक कैलेंडर को बाधित कर रहा है, जिससे केमस आगमन में देरी हो रही है और छात्रों में अनिश्चितता का माहौल है। अव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव:

पोस्ट
निर्धन नवीन की टीम की औसत आयु 5.4 साल है। यह एक तरह से भाषा का प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, जिसमें भाषाएं अपने मूल खिलौनों के अलावा बड़े स्टोको को भी तैयार कर लेना चाहती है। पीयूष पद्माकर @PiyushPadmakar

सरकार के नेतृत्व में युवा उद्यमी और नया सोच जरूरी है, जबकि किसी सार्वजनिक नेतृत्व में अनुभव, परिपक्वता और संगठनात्मक समझ का अपना महत्व है। दोनों स्तरों पर संतुलन ही किसी व्यवस्था को अपेक्षित स्तर से मजबूत बनाता है। डा. मीना कुमारी @DrMeenaJangid
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल एकबार नया शब्द देते हैं और यह बहुत तेजी से प्रारंभ में भी आ जाता है। विद्यार्थी से लेकर आलेखनकर्ता तक सभी को यह शब्द है। इस बार का शब्द 'निर्धन' नए तरीके से देखने लगा है। अर्धन नरवल या निरवल लेख लेते तो बहुत, लेकिन जगत के शब्द नहीं थे तो बुद्धिजीवी जगत के ही सीमित रूप पर। विभागी नरवल एकदम अनुभव पर चढ़ गया है। गाँवद रिसे @govind24

जागरण जर्मन कत का परिणाम

व्या मुक्त आनंदता कोविंग की पहल सामान्य कोविंग पर निर्भर घटने में सहायक बनेगी?



रमेश आनंद प्रतिभार में आज का सवाल

व्या निधन नवीन की टीम महित होने के बाद कैडियन मित्रियरिफ में फेरवदत के आसार बढ़ गए हैं। परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के फलदा का मत है।

जनपथ
नई-नवेली टीवी है करियर उसे प्रमोश, इसी टीवी से हो सफल भाई निधन नवीन। भाई निधन नवीन परीक्षा होगी गरीबी, इसी टीवी से आपा दौड़ की भरपूर गरीबी। अब मित्रियरिफ रानीत बनाइ डक अरवेली, जो दिवसए रोज सफलता नई-नवेली। -आम प्रकाश विवारी

आजकल

ब्रेन ड्रेन की दिशा में अमेरिका

अमेरिका की कठोर वीजा नीतियाँ तथा अनिश्चित प्रशासनिक माहौल भारतीय छात्रों के लिए एक बड़ी बाधा बनकर उभर रहे हैं। यह हालात न केवल व्यक्तिगत करियर के लिए, बल्कि अमेरिकी अव्यवस्था एवं नवाचार के भविष्य के लिए भी एक बड़ा खतरा है। ज्ञान तथा प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती है। यदि दरवाजे बंद किए गए, तो जो छात्र कल अमेरिकी आर्थिकी के स्तंभ बनने वाले थे, वे अब विश्व के दूसरे देशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे

अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले विदेशी छात्र केवल शिक्षा ग्रहण नहीं करते, बल्कि वे वहां की स्थानीय अव्यवस्था में अरबों डॉलर का योगदान भी देते हैं। वर्ष 2025-26 में अंतरराष्ट्रीय छात्रों ने अमेरिकी अव्यवस्था में 41.77 अरब डॉलर का योगदान दिया था। अब अनुमान है कि वर्ष 2026-27 तक यह गिरकर 38.37 अरब डॉलर रह जाएगा। इस गिरावट के कारण न केवल स्थानीय व्यापार प्रभावित होगा, बल्कि लगभग 39,000 नौकरियों पर भी खराब पड़ता रहा है। विशेष रूप से स्नातक स्तर पर नार्मकन में कमी, जो कि अनुसंधान और नवाचार का आधार है, दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान का कारण बनेगी। यदि अमेरिका वैश्विक प्रतिभा के लिए अपना शीर्ष स्थान खो देता है, तो आगामी बड़ी खोज या अविष्कार अमेरिका की भरती पर नहीं, कहीं और हो जाएंगे।

ओपीडी का भविष्य व सुरक्षा चिंता: ओपीडी (ओपनल प्रिंक्लिपेट ट्रेनिंग) कार्यक्रम के तहत डिग्री पूरी करने वाले छात्र अमेरिका में काम करते हैं। स्टैम (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिएटिक्स) क्षेत्र के लगभग 68 प्रतिशत ओपीडी प्रभावित भारतीय या चीनी हैं। इस पाठ्यक्रम को संतुलित करने से अमेरिका के अपने शीर्ष बाजार और तकनीकी क्षेत्र की बहुत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट में सुरक्षा चिंताओं को प्रमुखता दी गई है, विशेषकर चीनी छात्रों के संदर्भ में। इसमें तकनीकी हस्तारोहण, बौद्धिक प्रतिया वहां आते हैं जहाँ जसूसी जैसी चिंताओं का उल्लेख किया गया है। हालांकि यह सबसे संवेदनशील है, लेकिन इसका खामियाख भारतीय

छात्रों को भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि कठोर नीतियों का दायरा सभी एशियाई देशों के छात्रों पर लागू हो जाता है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में डिपार्टमेंट आफ होमलैंड रिकॉर्डीटी द्वारा किया गया यह निष्पत्ति कि अंतरराष्ट्रीय छात्र बिना विस्तार के जाएं सार से अधिक अमेरिका में नहीं रह सकते, पीएचडी करने वाले छात्रों और पीएचडी के बाद काम को तलाश करने वालों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यह निष्पत्ति छात्रों के सपनों को सोमित कर रहा है, जो अमेरिकी शोध संस्थानों और अस्पतालों का मुख्य हिस्सा हैं। डाक्टरेट और शोध कार्यक्रमों में लगे छात्रों के लिए चार साल की समय सीमा एक 'सिलिंग' को तह है। यह नीति उन मेधावी शोधकर्ताओं को हतोत्साहित करती है, जो जटिल वैज्ञानिक समस्याओं को हल करने में सक्षम होते हैं। कठोर वीजा नीतियाँ केवल कार्मिकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली व्यक्तियों के जीवन को दिशा तय करने वाली दीवार बन गई हैं। जब कोई देश अपनी वीजा नीतियों को इस तरह सख्त करता है कि वैश्विक प्रतिभा वहां आने से कतरने लगे, तो इसका परिणाम अंततः उस देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट के रूप में आता है। अमेरिका ने लंबे समय तक दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ दिमागों को अपनी ओर आकर्षित करने नवाचार में अपना लोहा मनवया है। फिलहाल, भारतीय छात्रों के लिए यह स्थिति एक कठिन समय है, लेकिन खास ही आत्मनिरीक्षण का अवसर भी है। क्या अमेरिका के अतिरिक्त विकल्प (जैसे कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया) अब अधिक आकर्षक हो सकते हैं? यह एक



जयकृष्ण वाजोपेयी
राज्य बोर्ड प्रमुख, बंगाल

को लकता की पिताहासन एक 'फेकमी आफ फाइन आर्ट्स' की सुरक्षा कक्ष की दीवारों का बोते एक माह में तीन बार बदलती हैं। पहले सफेद से भंगवा होना, फिर सफेद और फिर भंगवा रंगों का चट्टना केवल दीवारों का रंग बदलना नहीं है, बल्कि यह बंगाल की बदलती राजनीति की एक एसी इबात है, जो बौद्धिक जगत और सत्ता के बीच के समीकरणों में आए भारी भूचाल का दृश्य प्रमाण है। 1933 में लेंडी रात मुखर्जी द्वारा स्थापित और रवींद्रनाथ टैगोर एवं यामिनो राय की कलाकृतियों को धाती यह प्रमाण आज वैचारिक और राजनीतिक वर्चस्व का अखाड़ा बन चुका है। कभी वामपंथी संस्कृतिक वर्चस्व का गढ़ कहे जाने वाले बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग, जिन्हें कभी भारतीय संस्कृति का नैतिक कपास माना जाता था, आज पहले वैचारिक संकट और तबियत पर चढ़े होने की छटपटाहट से जूझ रहे हैं। यह घटना



इस बात का प्रतीक है कि कैसे बंगाल की राजनीति में अब 'पक्षता' और संस्कृतिक संस्थाओं की विस्थापन एक नए और आक्रामक दौर में प्रवेश कर चुकी हैं, जो यह बताता है कि बंगाल के संस्कृतिक इतिहास का सिरसा रंग तेजी से बदल रहा है। आजादी के बाद से ही बंगाल की राजनीति और बौद्धिक जगत का रिश्ता अटूट रहा है। करीब तीन शताब्दी तक चले वामपंथी शासन (1977-2011) के दौरान नाटक, सिनेमा, साहित्य और चित्रकला जैसे तमाम सांस्कृतिक क्षेत्र लाल (वामपंथी) कोटी की वैचारिक छत्रछाया में फले-फुले। बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे वामपंथी नेतृत्व के साथ कलाकारों और साहित्यकारों की अंतर्गतता जागजा रही। वामपंथियों ने इन बुद्धिजीवियों के सामाजिक प्रभाव का इस्तेमाल अपनी वैचारिक जमीन मजबूत करने के लिए किया, लेकिन जब 2011 में ममता बनर्जी ने वामपंथियों को हराया, तो उन्होंने इस रणनीति को और अधिक परिष्कृत कर दिया। गंगातीत व भद्रकाले समाजों को उस हिचक को भांप लिया,



संयन
सुमेष कुमार लकुर
रिसेरच स्कालर

वर्तमान में सरकारी नौकरियों में भर्ती व्यवस्था पर संकट केवल परे लोक या परीक्षा में धोखेती तक सीमित नहीं है। नई रितियों के लिए समय पर खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करने के बजाय बड़ी पुरानी प्रतीक्षा सूचियों से खाली पदों को भरना भी एक बड़ी समस्या है। ऐसी व्यवस्था में किसी परीक्षा की निष्पत्ता पर प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं होती और वहीं पुरानी प्रतीक्षा सूची के अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर ही मिल जाता है। यह स्थिति द्वारा प्रदान समान अवसर के सिद्धांत पर कुतरा जाता है। सरकारी भर्ती प्रणाली पर दोहरा दृष्टिकोण है। पहला, खाली पड़े सरकारी पदों को समय पर भरना और दूसरा, प्रत्येक पात्र नागरिक के लिए

समय पर भर्ती आवश्यक

नई रितियों के लिए वक्त पर खुली प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित कराने के बजाय वर्षों पुरानी प्रतीक्षा सूचियों से खाली पदों को भरना नए युवाओं से अवसर छीनने के समान है

सर्वजनिक रोजगार के द्वार खुले रहना। जब किसी प्रतीक्षा सूची का उपयोग वर्षों तक किया जाता है, तो इससे प्रशासनिक सुविधा अवश्य होती है, लेकिन इसके कारण नई पीढ़ी के अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी नौकरी के प्रवेश द्वार बंद होने जैसा हो जाता है। आज युवाओं में बेरोजगारी के कारण जो अस्तित्व व्याप्त है, उसका एक बड़ा कारण यह है कि नई रितियों समय पर अधिसूचित नहीं की जाती हैं, नई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित नहीं होतीं और वहीं पुरानी प्रतीक्षा सूची के अर्थव्यवस्था में नई उरणन रितियों पर नियुक्त किया जाता रहता है। जल्द ही यह उरणन रितियाँ, पर युवाओं को उनके लिए आवेदन करने और योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा। यहाँ से प्रशासनिक सुविधा का प्रश्न लोकतांत्रिक विचार के प्रश्न में बदल



सखी वीजा निर्णयों से भारत जैसे देशों के छात्रों के प्रवेश को मुश्किल बनाता अमेरिका।

प्रतीकात्मक

छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा में भारी कमी

पिछले वर्षों की तुलना में 2025 में भारतीय और चीनी नागरिकों को जारी किए गए एफ-1 स्टूडेंट वीजा की संख्या में काफी कमी आई है। 2024-25 शैक्षणिक वर्ष के दौरान अमेरिका के पोस्ट-सेकेंडरी संस्थाओं में एंजलि होने वाले सभी अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से आने से बचाव छात्र भारी और चीन से थे। 2017 से 2025 तक एफ-1 अगस्त की अवधि के दौरान जारी किए गए एफ-1 वीजा के नुस्तिरा इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल एजुकेशन की सालाना जनगणना के डाटा का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष (2024-25) के दौरान अमेरिका में भारत के 3,63,019 छात्र और चीन के 2,65,919 छात्र थे, जो कुल 11,77,666 विदेशी छात्रों का 53 प्रतिशत हिस्सा थे।

मई-अगस्त 2025 की अवधि के दौरान दोनों देशों के छात्रों को जारी किए जाने वाले एफ-1 स्टूडेंट वीजा में भारी कमी आई। आमतौर पर शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले इसी समय छात्र का यह जटिल संबंध अब एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर सुरक्षा के नवाचार संस्कृति को पुनर्जीवित नहीं किया, तो यह केवल भारतीय छात्रों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि स्वयं अमेरिका के लिए 'बौद्धिक प्रतिभा के पलायन' का कारण बनेगा।

एक अनिश्चित भविष्य की चुनौती: अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के बीच का यह जटिल संबंध अब एक चौराहे पर खड़ा है। एक ओर सुरक्षा के नवाचार संस्कृति को पुनर्जीवित नहीं किया, तो यह केवल भारतीय छात्रों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि स्वयं अमेरिका के लिए 'बौद्धिक प्रतिभा के पलायन' का कारण बनेगा।

सबसे ज्यादा स्टूडेंट वीजा जारी किए जाते हैं। अमेरिका ने मई और अगस्त 2025 के बीच भारतीयों को 22,149 एफ-1 वीजा जारी किए। यह संख्या 2017-19 और 2021-24 की अवधि में जारी किए गए औसत वीजा (55,717) की तुलना में 60 प्रतिशत कम है। यह संख्या 2024 में जारी किए गए 58,694 वीजा की तुलना में भी 62 प्रतिशत कम है। इसी अवधि में चीनी छात्रों को जारी किए गए एफ-1 वीजा की संख्या 2025 में घटकर 40,034 रह गई। यह संख्या 2017-19 और 2021-24 के औसत 73,853 से 46 प्रतिशत कम और 2024 में जारी किए गए 61,075 वीजा से 34 प्रतिशत कम है। 2024 में भारतीयों को जारी किए गए कुल एफ-1 वीजा में से 77 प्रतिशत और चीनी नागरिकों को जारी किए गए वीजा में से 76 प्रतिशत इसी अवधि में दिए गए थे।

2024-25 के दौरान अमेरिका में मौजूद दस लाख से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छात्रों में से 2,94,253 विदेशी छात्रों ने

अपनी डिग्री पूरी कर ली थी और वे ओपीडी के तहत काम कर रहे थे। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत भारतीय और चीनी नागरिक थे। इनमें भारत से 1,43,740 और चीन से 61,981 प्रतिभागी शामिल थे। 2024 में साइंस, मेडिकोलेजी, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंटस (स्टैम) ओपीडी में भाग लेने के लिए अधिसूचित 1,65,524 विदेशी छात्रों में से 68 प्रतिशत भारतीय या चीनी नागरिक थे। भारतीयों की संख्या 79,331 थी, जबकि चीनी छात्रों की संख्या 33,807 थी। तो पूरे एफ-1 वीजा प्रोग्राम के तहत हर साल 65,000 वीजा की सीमा तय है, मगर अमेरिका की एडवॉकेट डिग्री वाले विदेशी ग्रेजुएट के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा की छूट भी मिलती है, जबकि ओपीडी में कोई संख्यात्मक सीमा नहीं है। 2024 तक, ओपीडी और स्टैम ओपीडी के तहत काम करने वाले विदेशी नागरिकों की संख्या 5,05,590 तक पहुंच गई थी, जो एफ-1 वीजा प्रोग्राम के धीमाने के बराबर थी। (श्री राम शरा)

होगा। आज आवश्यकता है कि अमेरिकी नीति निर्माता इस बात को समझे कि ज्ञान और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं होती। यदि दरवाजे बंद किए जाएं, तो जो छात्र कल अमेरिकी अव्यवस्था के स्तंभ बनने वाले थे, वे अब विश्व के अन्य देशों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे और अमेरिका इस वैश्विक होड़ में पीछे छूट सकता है।

राजनीति का बदलता रंग



कोलकाता फेकमी आफ फाइन आर्ट्स को बदलता रंग।

फाइल

जो उन्हें 'शहरी-नर-कुलीन' घुड़धूम के कारण हाथिए पर रखती थी। ममता ने वाम-संस्कृतिकों के इस परे को तोड़ने के लिए कला-साहित्य जगत के दिग्गजों को खुले हाथों से आनवाया। उन्होंने नाटक, संगीत, चित्रकला और साहित्य की दुनिया के नामी चेहरों को अकादमियों में अग्रणी पद, सरकारी सिलीनियों और समारोहों में मंच पर बिठाया।

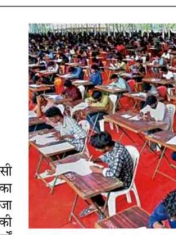
नरनंदयान किए गए या संकोच में रहने वाले कलाकारों, बुद्धिजीवियों को अकादमियों और भारी-भरकम सरकारी

अनुदानों से नवाजा गया। इसके बदले में तुलनापूर्ण वैचारिक को चुनौती दिया हो या संवेगवत भूराचार, सांस्कृतिक जगत के बड़े हस्ताक्षर एक सुविधाजनक चुप्पी साध गए।

कवि हो या चित्रकार, फिल्मकार हो या नाट्यकर्म-सरकारी मंचों और पुरस्कारों की चमक ने उनकी वैचारिक तीक्ष्णता को कुंठ कर दिया। तत्कालीन नरसीन के बंगाल प्रभाव पर प्रतिबंध या उदर सीरिलर के प्रसारण पर रोक लगाने पर जो स्वर वामकाल में गुंजते थे, वे तुलनापूर्ण शासन में गायब हो गए।

नतीजातन बंगाल की बौद्धिक दुनिया में एक अखंडित 'थ्रेट कल्चर' (धमकी के संस्कृति) ने जड़ें जमाई लीं, जिसके दबाव में आकर कई प्रतिष्ठित कलाकारों को सावजनिक रूप से अपनी असमर्थताओं पदवी पड़ी। यहाँ पर 2011 के राजनीतिक परिवर्तन और हालिया राजनीतिक परिदृश्य के बीच का फर्क स्पष्ट होता है। 2011 का बदलाव बुद्धिजीवियों की सक्रिय सहभागिता और परिवर्तन के मुखर नारों के साथ आया था। तब भद्रकाल का नागरिक समाज ने ममता बनर्जी को बदलाव के अग्रदूत

सड़कों पर उतरने के लिए जाना जाता था, वह भीम हो गया। योहो वह चुनौती दिया हो या संवेगवत भूराचार, सांस्कृतिक जगत के बड़े हस्ताक्षर एक सुविधाजनक चुप्पी साध गए। कवि हो या चित्रकार, फिल्मकार हो या नाट्यकर्म-सरकारी मंचों और पुरस्कारों की चमक ने उनकी वैचारिक तीक्ष्णता को कुंठ कर दिया। तत्कालीन नरसीन के बंगाल प्रभाव पर प्रतिबंध या उदर सीरिलर के प्रसारण पर रोक लगाने पर जो स्वर वामकाल में गुंजते थे, वे तुलनापूर्ण शासन में गायब हो गए। नतीजातन बंगाल की बौद्धिक दुनिया में एक अखंडित 'थ्रेट कल्चर' (धमकी के संस्कृति) ने जड़ें जमाई लीं, जिसके दबाव में आकर कई प्रतिष्ठित कलाकारों को सावजनिक रूप से अपनी असमर्थताओं पदवी पड़ी। यहाँ पर 2011 के राजनीतिक परिवर्तन और हालिया राजनीतिक परिदृश्य के बीच का फर्क स्पष्ट होता है। 2011 का बदलाव बुद्धिजीवियों की सक्रिय सहभागिता और परिवर्तन के मुखर नारों के साथ आया था। तब भद्रकाल का नागरिक समाज ने ममता बनर्जी को बदलाव के अग्रदूत



पार लोक की घटनाओं को रोकने की चुनौती। फाइल

निश्चित समय-सीमा के भीतर एक बार ओपरी वारमार्थ मौगी जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था को केवल उसके द्वारा चुने गए विभाग में जड़ें जमाई लीं, जिसके दबाव में आकर कई प्रतिष्ठित कलाकारों को सावजनिक रूप से अपनी असमर्थताओं पदवी पड़ी। यहाँ पर 2011 के राजनीतिक परिवर्तन और हालिया राजनीतिक परिदृश्य के बीच का फर्क स्पष्ट होता है। 2011 का बदलाव बुद्धिजीवियों की सक्रिय सहभागिता और परिवर्तन के मुखर नारों के साथ आया था। तब भद्रकाल का नागरिक समाज ने ममता बनर्जी को बदलाव के अग्रदूत

खरी-खरी

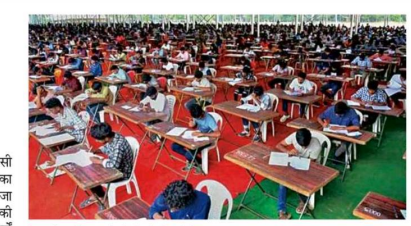
ममतामयी पलियां

अखिल पुरोहित

बेचारे पलियों को ड्रम से लेकर जमीन तक में गाड़ा जा रहा है, पहाड़ी से थकवा दिया जा रहा है, फिर भी अभी कई ममतामयी पलियां ने और गरजू पलियां ने सामाजिक संतुलन संभाल रखा है। हमारे एक सहकर्मियों अपना दुख पूरा करते थे। महीनेभर नौकरों की और एक तरीका को वेतन पत्नी को सौंप दे। किसी विचित्र कहानी है, हम पलियों की महीनेभर दिमाग लगाकर कलम विसर्ग और तनख्वाह बोली को सौंप दे। मैंने कहा बाई ऐसा नहीं है। पत्नी के हाथों में गृह और हित विभाग प्रारंभ से प्रकृति ने ही अल्ट्रा कर रखे हैं, लेकिन वे बोले- मैं क्या करूँ, घर की संसद में मैं भी अल्पमत में हूँ। बोली ने दोनों बेटियों एवं बेटे को, मैं तो गुलाम बाराहारा हूँ मैं उनसे सानुपुत्रि प्रकट कर आत्मविश्लेषण करने लगा। लगभग हर घर की यही कहानी है।

राज दायरथ की भी कैकेयी के कारण एक नहीं चल सकी, लेकिन इतिहास साक्षी है कि पत्नी का कहना नहीं मानने वालों का राणों की तरह अंत होता है। इस शाश्वतिक सेवकाल में प्रारंभ विभागीय प्रशासन में जाते रहते थे। हमारे सहकर्मियों उन प्रशासकों से बहुत खुश होते थे, क्योंकि पेलर पर आते हैं, घर फिर घर कि जेल में जाना ही है। मैं उनकी इस तरह की बातों से प्रभाव चिंतित नहीं हूँ। नरक-तुम क्रांति क्यों नहीं कर देते, आखिर मैं ही। वे दायरथिक मृत्यु में जाने और गुगुनगुनगुन लोहा-इस्क वो आसित है, जन्य, जो जालये न जले, दुष्पार न खुदें, यह कुछ भी हो हमें अपनी पत्नी से बेहतर प्यार है। यह भी सर है कि सप्ताह में इन दिनों महिलाओं की दायरथी चरम पर है। तो कुछ ममतामयी पलियों ने सामाजिक संतुलन संभाल रखा है। इन दिनों लोकप्रिय में निष्ठावत पदों पर पुनः पद बनने लगे हैं, सरपंच पति, पंचायत पति, विचारक पति। हमारे एक मित्र हैं, उनकी कालोनी में अच्छी भर्ती चलती थी, पर तुम्हारागुलाम हमरा बाई महिला आश्रित हो गया। नरार के आनुवंशिक कारण आखिर हर कैदी ममता, चुनाव जितावा हारा अपनी पत्नी को। पहले भी वे शेर की तरह चलते थे, अब बच्कर शेरों की तरह चलने लगे हैं।

के रूप में स्वीकार किया था, लेकिन हालिया राजनीतिक उलटपेच और भाषा के उभार ने इस स्थिति समीकरण को पूरी तरह उलट दिया है। भाषा ने बंगाल के इस पारंपरिक बाम-तुलनापूर्ण वैचारिक को चुनौती दी है, वह भी बिना पर्याप्त वैचारिक अभिजात वर्ग की वैसाखी के। आज वामपंथी प्रभाव पहले की संस्कृतिक केंद्र भी खुली राजनीतिक भिड़ंत के अखाड़े बन चुके हैं। रवींद्र सदन के पास स्थित प्रतिष्ठित 'फेकमी आफ फाइन आर्ट्स' की दीवारों पर रंगों का यह संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि बंगाल की सांस्कृतिक संस्थाएं अब वैचारिक तटस्थता छोड़ चुकी हैं। वामपंथी सांठों और भाषा के बीच सुरक्षा कक्ष के रंग को लेकर हुई रिसावकाली (एक महीने में तीन बार रंग बदलना) इसका प्रमाण है कि जमीन पर वैचारिक निष्पक्ष के लिए संघर्ष विमान तीव्र हो चुका है। आज बंगाली रिकाना पले को गुलाम में क्षीण हो चुका है। आज जनता और युवाओं के बीच अब इन पुराने आइकन की वह नरकिय धमक नहीं बची है। तुलनापूर्ण शासन के दौरान जो बौद्धिक युवा खुद को सत्ता के गहिरावों का संवेदनशील मान बैठे थे, वह आज एक बड़े वैचारिक चौराहे पर खड़ा है।



पार लोक की घटनाओं को रोकने की चुनौती। फाइल

निश्चित समय-सीमा के भीतर एक बार ओपरी वारमार्थ मौगी जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था को केवल उसके द्वारा चुने गए विभाग में जड़ें जमाई लीं, जिसके दबाव में आकर कई प्रतिष्ठित कलाकारों को सावजनिक रूप से अपनी असमर्थताओं पदवी पड़ी। यहाँ पर 2011 के राजनीतिक परिवर्तन और हालिया राजनीतिक परिदृश्य के बीच का फर्क स्पष्ट होता है। 2011 का बदलाव बुद्धिजीवियों की सक्रिय सहभागिता और परिवर्तन के मुखर नारों के साथ आया था। तब भद्रकाल का नागरिक समाज ने ममता बनर्जी को बदलाव के अग्रदूत



● हाल ही में लागू किया गया कृषिजाल अक्षरम सेशन दावा बना रहेगा। समस्याओं के समाधान के लिए हितवादी के फीडबैक का विचारलेखा किया जा रहा है।

— बुद्धि का प्रवेश, सेबी वेयरनेस



एक नजर में

नीति आयोग के नए सीईओ ने पदभार संभाला

नई दिल्ली: सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के नए सीईओ अनुराग जैन ने अपना पदभार संभाल लिया है। मध्य प्रदेश केडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासिक सेवा (आइएएस) अधिकारी जैन के पास सार्वजनिक प्रशासन, शासन और नीति निर्माण में लगभग चार दशकों का अनुभव है। जैन ने राज्य और केंद्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वे पहले मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और केड में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्य कर चुके हैं। (अनुरागखबर)

टैप्सर्स इंटरनैट्स ने तय किया शेयर की मूल्य

नई दिल्ली: आपगान और हीटिंग से जुड़े समाधान प्रदाता कंपनी टैप्सर्स इंटरनैट्स इंडिया ने अपने 650 करोड़ रुपये के आंशिक सार्वजनिक निगम (आईपीओ) का शेयर मूल्य 285-300 रुपये प्रति शेयर तय किया है। कंपनी का आईपीओ सार्वजनिक निगम के लिए 20-24 अगस्त तक खुलेगा। उच्च शेयर मूल्य के आधार पर कंपनी का अप्रैलित बाजार पूंजीकरण 2,515 करोड़ रुपये होगा। इस आईपीओ में 95 करोड़ रुपये के नए शेयर और 1.85 करोड़ प्रोबल्ट शेयर बिक्री के लिए पेश किए जाएंगे। (82)

एयरटेल पैमेंट्स बैंक के बोर्ड से हटते सुनील मित्तल

नई दिल्ली: भारतीय टेलीकॉम जेनरल के संस्थापक सुनील मित्तल एयरटेल पैमेंट्स बैंक के बोर्ड से हट रहे हैं। 30 सितंबर 2026 को नए-कार्यकारी चयन के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करेगे और बोर्ड से हट जायेंगे। बोर्ड की ओर से नियुक्ति और एनबीआई की मंजूरी के बाद शत्रुम सहा-एयरटेल 2026 के तीन वर्ष के लिए बैंक के चयनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। मित्तल को अप्रैल 2016 में एयरटेल पैमेंट्स बैंक का नए-कार्यकारी चयनक्रम नियुक्त किया गया था। (82)

सुपरटेक के पूरे निदेशक के बारे में 24 सितंबर को होगी सुनवाई

नई दिल्ली, प्रे: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य स्थापित काली एनबीसीसी को उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सार्वजनिक व्यक्तियों को, जिसमें एनकेएट के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, जिसने गुरुग्राम, पण्डित और ग्रेटर नोएडा समेत सुपरटेक लिमिटेड के 16 आवासियों प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए रद्द के तहत अनुमति से कोई भी फूट देने से इनकार किया था।

प्रधान न्यायाधीश सुब्रमण्यम, जस्टिस जगमोहन यादव और जी मोहन की पीठ ने राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई जारी किया और केंद्र सरकार और सुपरटेक के पूर्व निदेशक राम किशोर और सुपरटेक से जांच मांगा। एनबीसीसी के लिए उपस्थित अदालत निदेश आर.के.के.मिशन ने कहा कि मुद्दा रिजल एयरटेल (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 (रेग)

एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट में रेरा फूट के लिए दायर की याचिका, केंद्र और सुपरटेक से मांग जाव



के प्रमाणों से अनुमति में फूट देने से संबंधित है। पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर विचार 24 सितंबर को किया जाएगा और मामले को संबंधित मामलों के साथ सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने विधि अपीलीय न्यायाधिकार (एनकेएट) ने 12 दिवस, 2024 को केंद्रीय आवेदन और शहरी

मामलों के मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएचयू) एनबीसीसी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक में 49,748 प्लॉट के 16 आवासियों प्रोजेक्टों को पूरा करने का निर्देश दिया था।

लगभग 27,000 घर खरीदर इन प्रोजेक्टों में घर पानी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हजारों परेशान घर खरीदरों की मदद के लिए 5 फरवरी को शीर्ष अदालत ने एनकेएट के उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक के 16 आवासियों प्रोजेक्टों को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया गया था।

कोर्ट ने एनबीसीसी द्वारा पूर्ण किए जाने वाले निर्माण कर्तव्य को रोके जाने को भी आदेश पारित करने से सभी अदालतों को रोक दिया था। एनबीसीसी ने एनकेएट के समक्ष सुपरटेक के संबंधित प्रोजेक्टों को तीन चरणों में पूरा करने का प्रस्ताव दिया था।

लंबित परियोजनाएं

वरण एक के तहत एनबीसीसी ने ईको विलेज-2 (अंतर-नोडा), रोमानी (नोडा), केपटाउन (नोडा), काला रवीर (ग्रेटर नोडा), ईको विलेज-3 (ग्रेटर नोडा), सोलर्स विलेज (ग्रेटर नोडा) और इको-रिडि (नोडा) को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। वरण-2 के तहत एनबीसीसी ने एनकेट के समक्ष अपने आपोसे के अनुसार नोडा (नोडा), आकटी (कामा एनकोर्स), इको विलेज-1 (ग्रेटर नोडा), मेड सोलर्स विलेज (मेड) और ग्रीन विलेज (मेड) को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था। वरण तीन के लिए एनबीसीसी ने हिल्टनटाउन (गुरुग्राम), अरविली (गुरुग्राम), निरवकट (न्यूदु), इन न्यूवार्क (न्यूदु) और मिफ्टा (बंगलुरु) को पूरा करने का प्रस्ताव दिया था।

सरकार की सख्ती के बाद भी चीनी नगी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

केंद्र सरकार त्वाहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों पर नियंत्रण के लिए बाजार में उपलब्धता बढ़ाने एवं निर्यात रोकने का प्रयास कर रही है। फिर भी कीमतें न रफ्तार पकड़ ली हैं। पिछले एक महीने में चीनी का खुदरा मूल्य आठ प्रतिशत और थोक मूल्य सात प्रतिशत बढ़ा है। दिल्ली में भी खुदरा भाव 50 रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया है। केंद्र सरकार को आशंका है कि चीनी का प्यांव स्टॉक होने के बावजूद आपूर्ति रोककर कीमत बढ़ाने का खेल किया जा रहा है। ऐसे में कीमत पर नियंत्रण के लिए तीन स्तरों पर काम किया जा रहा है। इसमें चीनी मितलों के स्टॉक की जांच, ज्यारिरीयों के स्टॉक पर सीमा और बिक चुकी चीनी को अशंका बाजार तक पहुंचाना शामिल है। सरकार ने 24 जुलाई को देश की

- एक महीने में खुदरा मूल्य आठ और थोक मूल्य सात प्रतिशत बढ़ा
- कीमतों पर नियंत्रण के लिए तीन स्तरों पर काम कर रही सरकार



सभी चीनी मितलों में उपलब्ध स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने का फैसला किया गया। केंद्र एल राय सरकार की टीमां 14 अगस्त तक मितलों में जाकर वास्तविक स्टॉक की जांच की। अब रिपोर्ट का ईतराज है, जिससे बाजार की

स्थिति समझने में मदद मिलेगी। चीनी कार्यालयों पर भी शिकंजा कसा गया है। उनके लिए 30 अक्टूबर तक चीनी की अधिकतम स्टॉक सीमा 400 टन तक कर दी गई है। ताकि कालाबाजारी को प्रोत्साहन नहीं मिले। फिर भी कीमतों में तेजी नहीं आई। मितलों से बिक चुकी चीनी खरीदने वाले डीलर, एजेंट या थोक उपभोक्ता को सात दिन के भीतर ही चीनी उतानी होगी। बिक्री के बाद मितलों में चीनी को लंबे समय तक अपने परिसर में नहीं रोक सकते हैं, जिससे कीमतों की गुरुआत में बिक्री दिखाकर चीनी को मितलों में हो रोकने से बाजार में वास्तविक आपूर्ति कम दिखाई देती है, जिससे महंगाई को प्रोत्साहन मिलता है। राष्ट्रीय सरकार चीनी कारखाना माधवराव में भौतिक सत्यापन के आदेशों को सार्वजनिक करने की मांग की है। इससे अटकलों पर रोक लग सकती है।

लक्ष्मणन मरणपन वने दुनिया के सबसे कम उम्र के चार्टर्ड अकाउंटेंट

नई दिल्ली, जागरण: भारतीय मूल के 16 साल के एक युवक ने दुनिया का सबसे कम उम्र का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर इतिहास रच दिया है। लक्ष्मणन मरणपन का नाम दुनिया के सबसे कम उम्र के पुरुष चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) के तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स में दर्ज हुआ है। गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड्स के अनुसार, उन्होंने 16 साल और 141 दिन की उम्र में दुबई में यह उपाधि हासिल की है।

इंटरनेट मीडिया की खबरों के अनुसार, मरणपन की फाइनेंस में दिलचस्पी कोड-19 महामारी के दौरान, 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं पूरी करने के कुछ ही समय बाद जगी। उन्होंने 15 साल की उम्र में एसीआईएन एनएसएल चार्टर्ड सॉल्यूशंस अकाउंटेंट्स की तैयारी शुरू की और लगभग एक साल में यह कोर्स पूरा कर लिया। अभी 21 साल के हैं और दुबई में रहते हैं, जहां वे सेंचुरी फाइनेंसियल में सीनियर रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। उनकी जिम्मेदारियों में इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिसर्च और एनालिसिस करना, साथ ही फाइनेंसियल प्रोफाइल में फैसले लेने में मदद करना शामिल है।

तालाब में रहने को मजबूर बंगाल के किशोर का अनंत अंबानी की पहल पर मुंबई में होगा विशेष इलाज

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता: बंगाल में मुर्शिदाबाद के बेलडांगा के किशोर इकबाल को विशेष इलाज के लिए मुंबई लाया गया है। किशोर लंबे समय तक तालाब में रहने को मजबूर था। रिजल्टस इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक अनंत अंबानी के निदेश पर किशोर को एमएसएल कर मुंबई के सर एचएल रिजल्टस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डाक्टर उसकी जांच करेंगे और उपचार करेंगे। इकबाल के माता-पिता आर्थिक परेशानी के कारण लंबे समय तक उसका इलाज नहीं कर पाए थे। विशेषज्ञों ने लंबे समय तक पानी में रहने से होने वाले स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर चेतावनी दी थी।

तालाब में रहने का वीडियो हुआ था प्रसारित: बताया गया कि इकबाल कई दिनों तक तालाब में ही रहता था। उसका कहना था कि उसे ही वह पानी से बाहर आता है, उसके पैर शरीर में तेज जलन होने लगती हैं। उसमें यह भी बताया था कि उसे महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति का प्रभाव पर हो जा रहा है। इकबाल का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें वह तालाब में बैठकर खाना खाते हुए दिखाई दे रहा था। वीडियो सामने आने के बाद उसके मामले पर ध्यान दिया गया और मुंबई में इलाज करने की व्यवस्था की गई।

बैंकिंग सेक्टर में युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता

पीएसबी कान्फ्लुएंस 2026 के पहले दिन युवा पीढ़ी के लिए बैंकिंग उतावला तैयार करने पर चर्चा



- वित्त मंत्री ने कहा, विकसित भारत में बैंकों की भूमिका पर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन जल्द
- विकसित भारत के लक्ष्य हासिल करने के लिए बैंकों में बदलाव की सिफारिश करेगी कमेटी
- वित्तीय सेवा सचिव ने कहा, बैंकों को जमा जुटाने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी

नई दिल्ली में सोमवार को पीएसबी कान्फ्लुएंस को संबोधित करी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण • छद्मआइ

बैंकिंग में भारतीय युवाओं से जुड़ी चीजों को प्रमुखता से उठाने की दिशा में आजीवन पीएसबी कान्फ्लुएंस 2026 में इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया गया। कान्फ्लुएंस की शुरुआत के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा कि देश की आबादी में 15 से 29 साल के युवाओं की 29 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इसलिए भविष्य की

के बदलाव की आवश्यकता है। सीतारामण ने कहा कि इस कमेटी की सिफारिश पर तुरंत अमल शुरू किया जाएगा। विकसित भारत के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने की घोषणा इस साल एक फरवरी की यात्रा के दौरान की गई थी, लेकिन अब तक कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल बैंकों का गैर

निष्पक्षित संपर्क (एनपीए) अपने न्यूनतम स्तर पर है। इसलिए बैंकों को अब नए विचारों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। विकसित भारत के निर्माण में काफी बड़े पैमाने पर निजी की आवश्यकता होगी और इसके लिए मजबूत बैंक की जरूरत है। इस से-विश्वव्यापी कान्फ्लुएंस में सात मुद्दों पर बैंकों के बीच चर्चा

की जाएगी। सोमवार को जमा जुटाने, बैंकिंग घर वृद्ध, इन्वेस्टमेंट साइकल, वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मॉललवार को बचे हुए तीन मुद्दों एपी वेल्यू चैन इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्राथमिक क्षेत्र की कर्ज और क्रेडिट काई बिजनेस के नई शुरुआत पर चर्चा होगी। इस मौके पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव संजय लोहिया ने कहा कि बैंकों को जमा जुटाने के लिए नए तरीके के साथ ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने बताया कि बैंकों का कारोबार बढ़ने के साथ मुनाफा भी लगातार बढ़ रहा है।



बिजनेस से जुड़ी खबरी और अपडेट के लिए खबरें का बिजिट कर jagran.com

बेरोजगारी दर जुलाई में घटकर 5.1% रही

नई दिल्ली, प्रे: इस वर्ष जुलाई में 15 वर्ष और इससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कुल बेरोजगारी दर घटकर 5.1 प्रतिशत रही है, जो इसी वर्ष जून में 5.5 प्रतिशत थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी किए गए आर्थिक श्रम बल सर्वे में यह जानकारी सामने आई है।

सर्वे के अनुसार, पिछले महीने ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 4.5 प्रतिशत रही, जो जून 2026 में पांच प्रतिशत थी। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर जुलाई में 6.7 प्रतिशत पर स्थिर रही, जबकि जून में यह 6.6 प्रतिशत थी। जुलाई 2025 की तुलना में, कुल बेरोजगारी दर और ग्रामीण बेरोजगारी दर पिछले महीने स्थिर रही है। जबकि शहरी बेरोजगारी दर जुलाई 2025 की 7.2 प्रतिशत से घटकर जुलाई 2026 में 6.7 प्रतिशत पर आ गई। सर्वे के अनुसार, पिछले महीने ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और पुरुषों की बेरोजगारी दर घटी है। वहीं, शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर में कमी आई है।

इस वर्ष त्वाहारी सीजन में सृजित होंगी 2.7 लाख नई गिंग नौकरियां

वर्ष 2026 के त्वाहारी सीजन (अगस्त से नवंबर) के दौरान अस्थायी स्टाफ या गिंग वर्कर्स की मांग में सालाना आवां पर 15-20% की वृद्धि होने का अनुमान है। टैटेंट कंपनी एडको इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान 2.5-27 लाख नई गिंग नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। इसमें ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र का प्रमुख योगदान रहेगा। पिछले वर्ष त्वाहारी सीजन के दौरान 2.16 लाख नौकरियां सृजित हुई थीं।

15-20 प्रतिशत की वृद्धि संभव गिंग वर्कर्स की मांग में सालाना आधार पर



2.16 लाख नई नौकरियां सृजित हुई थीं पिछले वर्ष त्वाहारी सीजन के दौरान

टिप्पणी-2 3 शहरों से कार्यवली की ज्यादा मांग

रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष लगभग 45% इंडियन की मांग टिप्पणी-2 और टिप्पणी-3 जैसे शहरों से आएगी। इसमें लखनऊ, भुवनेश्वर, जयपुर और कोयंबटूर जैसे शहर शामिल हैं। इन शहरों में गिंग वर्कर्स की मांग को बढ़ावा देने के लिए नए पद्धत और समर्पित खुदरा कारोबार के विकास का समर्थन मिलेगा।

टिप्पणी-1 शहरों में टैटेंट की ज्यादा कमी

रिपोर्ट में कहा गया है कि टिप्पणी-1 शहरों में गिंग वर्कर्स के वेतन में 12-15 प्रतिशत और टिप्पणी-2 3 शहरों में 8-10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि इस साल हारायरी नई श्रेणी के बलाय अमर संचालन और गिंग कार्य के प्रति बढ़ती प्राथमिकता के कारण टिप्पणी-1 शहरों में लोगों को काम पर रखना और उन्हें बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया है।

मेट्रो शहरों में वेतन 12-15 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद

रिपोर्ट के अनुसार, मेट्रो बाजारों में गिंग वर्कर्स के वेतन में 12-15 प्रतिशत और टिप्पणी-2 3 शहरों में 8-10 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि इस साल हारायरी नई श्रेणी के बलाय अमर संचालन और गिंग कार्य के प्रति बढ़ती प्राथमिकता के कारण टिप्पणी-1 शहरों में लोगों को काम पर रखना और उन्हें बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया है।

बहुभाषी उमीदवारों की ज्यादा तलाश

कठिनाई आर कई भाषाएं जानने वाले उमीदवारों को ज्यादा परफॉरमेंस की उम्मीद है। रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि इस साल हारायरी नई श्रेणी के बलाय अमर संचालन और गिंग कार्य के प्रति बढ़ती प्राथमिकता के कारण टिप्पणी-1 शहरों में लोगों को काम पर रखना और उन्हें बनाए रखना और भी मुश्किल हो गया है।



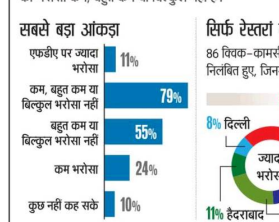
इस वर्ष के त्वाहारी सीजन में हारायरी की मश जटिल वैश्विक व्यापार वातावरण के बावजूद मजबूत बनी हुई है। फेरुलु क्वांट रिजल, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अन्य उद्योगों-आधारित क्षेत्र से मांग आई है। निर्यातक भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वताओं, ऊर्जा मूल्य में उतार-चढ़ाव और निर्यात-आधारित उद्योगों में निरंतर अनिश्चितता के बीच अधिक सर्वकारी से रोजगार बना रहे हैं।

— दीपिका गुप्ता, निदेशक, एडको इंडिया

इनपुट-प्रे: जागरण इनको

छापो खूब पड़ रहे हैं... फिएर एफडीए पर भरोसा क्यों नहीं?

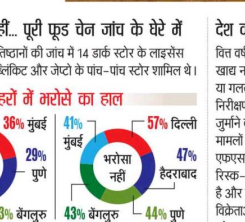
रेस्तरां, होटल, डाई रेस्तरां और मोदामों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लाइसेंस निलंबित हो रहे हैं, खाद्य सामग्री जब्त की जा रही है। फिर भी लोकल सर्विसेज के ताजा सर्वे में 322 जिलों के 22,819 परभावताओं से प्रतिप्रतिक्रिया मिली। जिसमें 11 प्रतिशत लोगों ने अपने जिले/राज्य के खाद्य एवं औद्योगिक प्रशासन (एफडीए) पर ज्यादा भरोसा बताया। वहीं 79 प्रतिशत का भरोसा कम, बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।



कार्रवाई पर सवाल: बाबू बाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए की कार्यवाही में सुधार सुचना व सुनवाई की प्रक्रिया का पालन न होने पर सवाल उठाए। होटल-रेस्तरां संगठनों ने भी खाद्य सुरक्षा और भ्रमक अधिनियम, 2006 की सेक्शन 32 के तहत उचित प्रक्रिया की मांग की है। कोर्ट एक होटल का लाइसेंस निलंबन रद्द कर चुका है।

सर्विसेज रेस्तरां नहीं... पूरी फूड चेन जांच के घेरे में

86 विद्यमान-कामगार प्रतिनिधियों की जांच में 14 डाई रेस्तरां के लाइसेंस निलंबित हुए, जिनमें बिलिफेट और गेहूं के पांच-पांच स्टोर शामिल थे।



कार्रवाई पर सवाल: बाबू बाई कोर्ट ने महाराष्ट्र एफडीए की कार्यवाही में सुधार सुचना व सुनवाई की प्रक्रिया का पालन न होने पर सवाल उठाए। होटल-रेस्तरां संगठनों ने भी खाद्य सुरक्षा और भ्रमक अधिनियम, 2006 की सेक्शन 32 के तहत उचित प्रक्रिया की मांग की है। कोर्ट एक होटल का लाइसेंस निलंबन रद्द कर चुका है।

देथ की तस्वीर

दिल्ली में 2025-26 में जांचे गए 2,23,808 खाद्य नमूनों में 40,023 असुरक्षित, पाँच या गतल बेतल वाले पाए गए। 1,20,566 निरीक्षण हुए और 31,878 रिजल्ट मामलों में गुंजायिरी का फैसला हुआ, लेकिन अपात्रता मामलों में सिर्फ 1,918 दोषनिर्दिष्टा हुई। एफएसएसआई ने टेकोलाजी-इनेवेल, रिस्क-बेसड इन्फेक्शन रिस्कअन आया है और राज्य को मॉड्यो, क्वाथे, दूध क्रिस्टलाइज और शिफ्टको पर निगरानी बढ़ाने को कहा है। फिर भी रक्खरा रीजग योजना अभी रोकथाम है। आम ग्राहकों को यह पता नहीं चलता कि किसी रेस्तरां, दुकान या डाई रेस्तरां की आडिरी जांच कम हुई और उसमें क्या मिला।

चंडेराजनेन ने अपना वर्तमान कारकवल समायोप होने के बाद एक और कारकवल की मांग न करने का फैसला किया है। कंपनी की ओर से पहले जारी नोटिस के अनुसार, एजीएम मॉललवार दोहतर 2330 बजे मॉड्यो की कंसिंसिंग या अन्य आडिरी-विशुलल माथमयों में जांचे आवांशित की जाएगी। इन्फेक्शन बायोलॉजिस्ट, बायॉफॉस आम बैक्टीरिया के क्लॉन के वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सांख्यिकी शरीरों पर लायोलॉजी घोषणा और बीते वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर विचार व मंजूरी लिया जाना है। अब आर बैक्टीरिया पर उत्तर रहेगी।

भाजपा की नई टीम

भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई सांगठनिक टीम का ऐलान कर दिया है। हालांकि, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी को अपनी नई टीम बनाने में छह महीने से ज्यादा बकल लगा, पर अगर वो टीम सामने आई है, वह समग्रता में जरूरी सिखासी पैमानों पर संतुलित नजर आती है। जाति, जनजाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग को बेहतर समन्वय नई टीम में दिख रहा है। भाजपा अध्यक्ष युवा नेता और वह आगामी चुनावों को लक्ष्य बनाकर अपने बढ़ते दिख रहे हैं। पांच बार विधायक रहे और अब राज्यसभा सांसद नितीन गडकरी ने सौच-विचारकर्ता को बल बनाई है, उसकी विवेचना अलग-अलग ढंग से हो सकती है। बहरहाल, टीम में कुछ कमजोर चमकदार हैं, तो अनेक नाम पार्श्व में रहकर काम करते रहेंगे। टीम बनाते समय अनुभव, समीकरण और वर्तमान छवि को ध्यान में रखा गया है। पुरानी टीम में भी जमीनी स्तर पर काम करने वाले नेता थे और उस टीम से करीब एक चौथाई नेता नई टीम में लिए गए हैं। कुल मिलाकर, वो टीम बनाई गई है, वह पुस्तुकी से काम करे, तो इन दिनों कुछ मुश्त पर धिरेती दिख रही भाजपा को बल मिलेगा।

नई टीम में सबसे बड़ी खुशी यह कि 12 महिलाओं को पदाधिकारी बनाया गया है। इनमें सर्वाधिक परिचित-चर्चित नाम वसुंधरा राजे सिंधिया और स्मृति ईरानी का है। पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्र में मंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति

अपनी नई सांगठनिक टीम का गठन करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक इंजीनियरिंग के हिसाब से सिखासी संतुलन बिठाने की कोशिश की है।

ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव। दोनों ही नेताओं को जमीनी राजनीति और सरकार में रहने का अनुभव है, दोनों को मुखरता के लिए जाना जाता है। कौसे दारांग नई कि आज भाजपा नेतृत्व में मुख्य मंत्रि गतेताओं की जगहल है। नई टीम का गठन करते हुए भाजपा ने सामाजिक इंजीनियरिंग के हिसाब से काम किया है। विचारवान भाजपा नेता राम माधव को उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिजल देव राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोस्वामी को फिर एक बार कोषाध्यक्ष नियुक्त करने के

अपने मायने हैं, तो सांसद अजित भट्टानी के पास भीडिंगाभाभार बकावर रखा गया है। एक बड़ा बदलाव भाजपा आईटी सेल के मुखिया अमित मानवीय को विदाई है। वह साल 2015 से आईटी सेल संचालन रहे। बदलती जरूरतों के मुताबिक अब वह अहम काम नई टीम को हलाल किया गया है, तो आने वाले दिनों में भाजपा की आईटी नीतियों-नीतियों में बड़े बदलाव और ताजगी को संभालने हैं।

आज पार्टी के 46 वर्षीय अध्यक्ष के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। पहला, संगठन को पुनः मजबूत व ज्यादा सक्रिय करना और दूसरा, पार्टी की अपनी सुविधित छवि का संरक्षण व संदंडी करना। पार्टी को सत्ता का स्वाद चखते 12 साल से ज्यादा बीत गए हैं, तो स्वाभाविक ही विरोध और विरोधियों का आकार बढ़ने की आकांक्षा दिख रही है। अपने चिंतित दलीय अनुशासन और दूसरों से अलग खड़े को कायम रखने के लिए उसे खुद को समर्थ के अनुरूप पुनर्बना करना पड़ेगा। शायद अपना आकर्षण बनाए रखने के लिए ही भाजपा के शीर्षनेतृत्व ने दूसरे दलों की तुलना में ज्यादा युवा अध्यक्ष पर भारीका किया है। नई टीम वाली बात होगी कि युवा अध्यक्ष की नई टीम सुझाव रूप से देश के युवाओं की कितना आश्चर्यकर का पाती है? नई टीम मुखरता के लिए भाजपा की यह नई टीम सत्ता में बैठे केंद्रीय और क्षेत्रीय अला नेताओं से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ना चाहेगी। इन दिनों में सबसे पहली और बड़ी परीक्षा होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव।

हिन्दुस्तान 75 साल पहले 18 अगस्त, 1951

भारतीय मुसलमान

भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव भारत के चार कोड़ मुसलमानों के लिए विषम रूप से चिन्ता का विषय है। भारतीय मुसलमानों ने आम तौर पर मुस्लिम लीग का समर्थन किया था और पाकिस्तान की स्थापना की हिममत की थी। किन्तु जब दोष का विधान बन गया और पाकिस्तान की स्थापना हो गयी, तो भारतीय मुसलमानों से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने अपने धर्म महसूस की, किन्तु बाकी हथ से निजल चुकी थी और कुछ समय तक उन्हें अत्यन्त विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उन्होंने देश की लौंगी तान भारतीय मुसलमानों को अपने हाल पर छोड़कर पाकिस्तान के अपने नये चमन में बस गये। भारतीय मुसलमानों ने अपने पाकिस्तानी हम-मजबूतों से बार-बार अपील की कि उन्हें भारतीय मुसलमानों की हालत पर सरत खाया चाहिए, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए, जिसका उन्होंने रसिमत पर प्रतिक्रिया असर पड़े। किन्तु इन प्रकार की सब अपीलें बहरे कागज पर पड़ीं और भारतीय मुसलमान अब अपने पुराने देशों के व्यवहार से घृनि तरबित हैं।

भारतीय मुसलमानों की ओर से समुद्रत राष्ट्रीय प्रतिनिधि डा. शमम को एक स्मरण-पत्र लिखा गया है। इस पत्र भारत के 15 मुस्लिम नेताओं के हस्ताक्षर हैं, जिसका भुक्ताल में देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में विघटित स्थान रहा है और आज भी वे उच्च स्थानों पर आसीन हैं। वह विषयवस्तुओं के कक्षा जा सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान की भारत-विरोधी नीति के बारे में अपने स्मरण-पत्र में जो कुछ कहा है, वह भारतीय मुसलमानों के वर्तमान विचारों का सही प्रतिनिधित्व है। स्मरण-पत्र का कहना है, "पाकिस्तान की नीति अलग तौर पर और काश्मीर के प्रति उदासीन रवैया हमारे नैतिक हितों के खिलोफ़ कर रही है। हमारे अन्तर्गत हम भारतीय मुसलमानों को व्यापक स्वर-सहन और तलाशी का सामना करत पड़ेगा। पाकिस्तान की नीति के कारण हम निश्चिन्त नहीं हो सकते हैं, वह अपने राज्य के सामान्यप्राप्त नागरिकों के बने बने हमारे लिए बाधक हो रही है। वह हमको अपने देशवासी होने के संकेत का हिसाक बतौती है और हम अपने देश का हित बनाए रखने के लिए बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने को नहीं बदल सकते।"

आधुनिक समाज में मर रही संवेदना

माता-पिता अपने बच्चों की परवरिश में जिंदगी का हर कुछ भूल जाते हैं। उनकी आंखों में बस एक प्रेम होता है कि बच्चे बड़े होकर सफल हो और जीवन की उल्लती धारा में उनका सहायक बने। इसी उल्लती धारा में अपनी इच्छाओं की पीढ़ी छोड़कर बच्चों के भविष्य के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। ऐसे में, जब बड़े संतान दुबारा में हमला धायेने के बजाय उन्हें दूर जा देना, जब उस अकेलपन का दर्द किन्ता महार होता है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।

हाल ही में सोनीपत के एक व्यक्ति का मामला रिश्तों की बदलती रवियी पर सोचने को मजबूर करता है। कभी मुंबई के बड़े कामड़ा व्यापारियों में शुमार रहे व्यक्ति फिलहाल तीन वर्षों से सोनीपत स्थित एक वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। उनकी तीन बेटियां हैं। उन्होंने बेटियों को कपड़ा-निखाना, उन्हें आलसपूर्ण बनाया और जीवन में

आगे बढ़ने में लिए हर्षसंपन्न अस्वर दिया। जिस पिता ने अपनी तीन बेटियों को उंगली पकड़कर चमकता सिखाया और उनकी सफलता, उन्हीं ने उसे आखिरी सफर में भी अकेला छोड़ दिया। पिता जिन्दा होने के अंतिम घण्टी पर उनका ईश्वरानु कता रहा। बीमारों में बेटीयां मिलती नहीं आईं और अंतिम विदाई भी नाथीयों को दे दी। दो वर्ष पहले इसी घृणाघर में उनकी पत्नी भी अंतिम सांस ली थी। पत्नी के जाने के बाद शायद बेटियों का साथ उनके लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया होगा। उस के पस पड़ाव पर उन्हें पता चला होगा। उस के अन्त होकर लंबा होना चला गया। 20 दिनों तक बीमार रही। आश्रम प्रबंधन ने वह सुनाना बेटियों को बार-बार नहीं दूना है कि आमतौर के दौरान बेटियों ने प्लेन पर बातचीत करती भी बंद कर दी।

विजय सरकार में सौ दिन का हासिल



एस. श्रीवास्तव। बरिष्ठ प्रकाश

अभिनेता से नेता बने श्री गोलोक विजय की सरकार ने तमिलनाडु को सत्ता में 100 दिन पूरे कर लिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनके सुधारवादी होने की वजह से उन्हें अपनी पार्टी बनाने के दो साल के अंतर ही सत्ता मिल गई, मगर जब विजय की सरकार ने आगे वह शासन की संसदीय पर भी खर उतरा कि किसी भी सरकार के कामकाज का अकलतन करने के लिए बहुत काम है, लेकिन इससे सरकार की सोच की एक झलक जरूर मिल जाती है। चुनाव जीतना एक बात है, जबकि कठोर जमीनी संचाई के बीच अपनी राजनीतिक छवि को बनाए रखना विजय का अलग। उनके शासन के तरीके का अंदाजा अब तक के कार्यकाल से लगाया जा सकता है। विजय ने जब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तब से पूरे देश की नजर उनके शासन करने के तरीके पर टिकी है। उनका सत्ता में आना तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। वहां की सत्ता पर प्रश्नों से प्रेरित पार्टीयों का कक्षा रहा है। द्रविड़ मुन्नेत्र कणम (द्रमुक) के सत्ता में आने के बाद पहली बार राज्य में ऐसी पार्टी की सरकार बनी है, जिसके नाम में 'द्रविड़' शब्द नहीं है। शायद प्रश्न के बाद विजय ने कहा कि वह अपने वार्डों को पूरा करने के लिए जनता से धीरे-धीरे काम की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने जनता से किताबें खरीदें पर काम करना शुरू भी कर दिया है। आज उन्होंने करीब साढ़े तेरह लाख किसानों के 75,000 रुपये का कृषि-कर्म-कार्य करने की घोषणा कर दी है।

विजय के लिए सत्ता बनाया आसान न था, क्योंकि दो साल पहले ही वह चुनावी राजनीति में आए थे। हालांकि, जलवीरुद्र प्रियदर्शन की तरह एक ठक्कर शामिल होकर और साल 2008 में श्रीलंकाई तमिलों के समर्थन में अठर पट्ट में कुछ-न-कुछाल करके उन्होंने शासन में अपने के संकेत दे दिए थे। किसी स्टारडम से राजन-प्रशासन की कूटनीतिक गलियों में आना कोई रास्ताल का खेल नहीं है। इसलिए, निरविकर रूप से

‘संगठित षष्ठाचार’ को खत्म करना तमिलनाडु की विजय सरकार के अहम नारों में से एक रहा है। जनता से जुड़े कुछ सरकारी विभागों में छोटे षष्ठाचार में कमी दिखने लगी है।



नहीं कहा जा सकता कि वह सरकार सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में, क्योंकि वह अभी 'काम प्रगति पर है' वाली स्थिति में है। शासन-व्यवस्था की बात करें, तो इसमें कानून-व्यवस्था, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक समता और सामाज्य प्रशासन जैसी कई जरूरी मुद्दों पर काम करने पड़ेंगे। इसके ऊपर एक और मुश्किल राजनीतिक मुद्दा है- अपनी टीम को एकजुट करना। चूंकि, टीवी के सरकार अल्पमत में है, इसलिए शासन चलाने के साथ-साथ सत्ता पर पकड़ मजबूत बनाया विजय की दोहरी चुनौती है।

अभिनेता से वरिष्ठ पत्रकार पर द्वितीय टिप्पणी के आगे व विजय के नेता उर्वरविद्वान् स्टालिन को हिरासत में लेकर विजय ने गलत काम किया। उन्होंने टिप्पणी अल्पमत, पर शक्ति मानवनिर्माण भाग को आग्रह की अंशों में सत्ता की सरकार की कौशलशक्ति की उनकी ही निंदनीय है। उन्हें पर से उठकर शहर के दूसरे कोने में स्थित पुलिस स्टेशन जाने के बजाय महाश्वीन के कानूनी धाराओं से भी वही काम किया जा सकता था। हालांकि, सरकार ने तुरंत जोरें हटकर इस घटना

को बड़ा संकेत बनने से रोक लिया। सरकार ने अदालत को बताया कि 'उन्हें केवल पुछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।' उन्हें उसी दिन रिहा कर दिया गया। टीवी के पर पुराने मुद्दों को दोहराने के आरोप लगे हैं, जैसे राज्य विधानसभा में नीट और 'तमिल थाई वानु' (राज्य गीत) के मुद्दों को उठाना, जिसका इस्तेमाल द्रमुक और अनाद्रमुक सालों से करते आ रहे हैं। कई अलोचकों का कहना है कि सरकार को राज्य काद्र आर्थोनिट परीक्षाओं की गुणवत्ता सुधारने, छात्रों को नीट के अलावा अन्य प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने, रोजगार विहीन युवाओं के सरकारी भित्तियों पर रोक जैसी समस्याओं से जुझ रही 'जेन-जी' को रोजगार तमिलनाडु बनाकर था। हालांकि, वह आलोचना तमिलनाडु की राजनीति को न समझने के कारण है। वहां पर इन मुद्दों को नजर अंदाज करना अल्पमत के लिए बुरा नहीं है। 'बोरिंग्स' अधिकारियों की टीम नहीं है, क्योंकि वर्तमान अधिकारियों में से ज्यादातर था तो द्रमुक या अनाद्रमुक सरकारों के साथ काम कर चुके हैं। उनकी असली परीक्षा यह है कि क्या वह ऐसे

नौकरशाहों और शिक्षित सोसायटी के लोगों को साथ जोड़ सकते हैं, जिसकी सोच उनकी राजनीति से मेल खाती हो। विजय सरकार द्वारा सत्ता पहल वजह को 'रिक्टर आर्गे' (पूरा नीति योजनाओं के साथ रिक्टर चिह्नकार अपनी योजना बनाता) कहा जा रहा है। यानी, उनकी छुछ योजनाएं असर में अनाद्रमुक और द्रमुक की कक्षायोजना योजनाओं का ही स्या रूप है। सामाजिक कल्याण द्रविड़ युवाओं का मुख्य आधार रहा है। पक्कालाओ की मिस्टर-माईड योजना ने महिलाओं के विना वेतन वाले रोजों के काम को नतीजा आसान कर दिया था। 'मिल-नट्टे' पर हाथ से मसाला पीसने से उन्हें आजाद मिल गई।

असम में, टीवी के योजनाओं को लागू करने में चुक गई है। मौजूदा योजनाओं की समीक्षा के लिए सौ दिन का हवा हुआ है, पर ऐसा कोई प्रसन्न नहीं किया गया। इसका नतीजा हुआ है कि नवनात विधायों के लिए सत्ते की अंगुठी देने वाली सत्ता योजना विजय कमी के कारण सिर्फ सरकारी अस्पतालों में पैदल हुए बच्चों तक सीमित हो गई है। तमिलनाडु सरकार ने फंड जुटाने के नए तरीके खोजने के लिए मॉडर्न सिंह अल्लुवियाणा की अध्यक्षता में एक वाजव्य समिति गठित कर दी है।

इसी तरह, 'संगठित षष्ठाचार' को खत्म करना विजय सरकार के सबसे अहम नारों में से एक रहा है और इसकी ताकत सोचे उनको सरकार एवं 'बिलिंग जैसी फिक्सी' में 'न्याय के पीपल' और 'भट्टाचार विरोधी' को भूमिका वाली छवि से मिलती है। लोग अब असल जिंदगी में भी थोड़ा थोड़ा निभाते की उमीद करते हैं। इस उमीद के पराप्त पलटने के कुछ शुरुआती सूत्र मिल रहे हैं। जनता से सोचे जुड़े कुछ सरकारी विभागों के छोटे-छोटे षष्ठाचारों में समर्थता कमी आई है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि षष्ठाचार से लड़ना इतना आसान नहीं है।

पूरी बहुमत पर दिए गए उन उपा-युक्तों में जाना होगा। चूंकि वह अब लोकप्रिय है, इसलिए उन्हें बहुमत मिल सकता है। परीक्षाओं और कांवेरी तल विचार के मुद्दों पर वह सत्ता रखे हैं। मुश्किल काम केंद्र व कांवेरी के बीच सत्ते संतुलन बनाए रखने और द्रमुक पर नजर रखना है। उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि हार से आहत वेनो द्रविड़ भाईयां कक्षा करने के मौक की तलाश में हैं। इससे अलग बात यह कि युवाओं की उम्मीदें बढ़ाने के बाद अब विजय की नतीजें देनी होंगी। (य लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

मन बिखर न पाए

मनोविज्ञान को गुंथ से देखें, तो हमारे मन में दो पक्ष होते हैं-विषय और विषय का जाल। जो कुछ हम देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, वह हमारे लिए विषय है, जो उसे देखता, समझता और जानता है, वह हमारा जाल है। सरल शब्दों में कहें, तो वस्तु नहीं जानती है और मन उसे जानता है।

इसे एक उदाहरण से समझिए। सांभं मेंहैक को देखता है। वहां सांभं विषय है और ठेक उसे लिए वस्तु। मेंहैक मच्छर को देखता है, इसलिए मेंहैक विषय और मच्छर वस्तु है। मच्छर और ठेक को देखता है, तो मच्छर विषय और ओस की बूंद वस्तु बन जाती है, पर क्या सांभं को पता है कि मच्छर को देखता है और क्या मीर को मालूम है कि मीर की उस पर नजर रहने हुए है? यहां रिश्ता विषय है और मीर उसका विषय।

हम सामान्यतः विषय को देखते हैं, लेकिन वह देखने वाले को नहीं जानते। हम दुनिया को देखते रहते हैं, पर इसे देखने वाला मन स्वयं भावों की दृष्टि से अछल रहता है। यदि मनुष्य अपने भीतर के इस 'जाल' को देखने और समझने का प्रयास करे, तो उसके जीवन में अधिक स्पष्टता और संतुलन आ सकता है। दार्शनिक नूट से कहा गया है कि हमारा को समझने वस्तु एक विगत मानसिक सत्ता के भीतर है, अर्थात् जो कुछ हम संसार में देखते हैं, वे सभी जो हम पर चेतना के लिए 'विषय' हैं। हम किसी वस्तु को जानते हैं, लेकिन स्वयं हमारे अस्तित्व को किसी विचार चेतना द्वारा जाना रहा है। इस प्रकार व्यवहारगत और परम चेतना के बीच भी जाता और जेन के संबंध बनाया जाता है।

अब इसे रोजमर्रा के जीवन में जोड़कर देखें। मान लीजिए, एक विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। उस

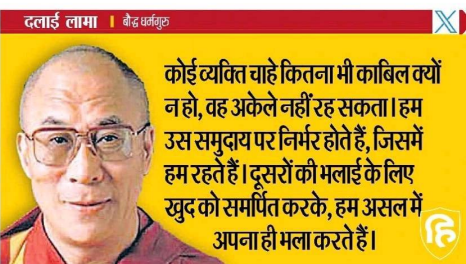
किताब पढ़ते समय बार-बार वह चिन्ता सताती है- 'अगर मैं असफल हूँ, तो माता-पिता क्या कहेंगे? पड़ोस फिर से उसी काम में पड़ना पड़ेगा। छोटे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। समाज में मेरे प्रतिभा को भी जायागी।' वे विचार अपने अपने में असामान्य नहीं हैं। समस्या तब पैदा होती है, जब पढ़ाई के समय मन को धीरे-धीरे उस समस्या में लगा हो और दूसरा सफाई की कल्पना में। मन की शक्ति दो दिशाओं में बंटा जाती है। परिणाम

जीवन के हर क्षेत्र में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को बिखरने से कितना बचा पाते हैं। जब मन वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित रहे, तब ज्ञान गहरे उतरता है।

वह होता है कि न तो पढ़ाई पूरी तरह हो पाती है और न ही चिन्ता समाप्त होती है।

जीवन के हर क्षण में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को बिखरने से कितना बचा पाते हैं। जब मन वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होता है, तब ज्ञान अधिक गहरे से घीर उतरा उभरता होता है, जब ज्ञान अधिक गहरे से घीर उतरा उभरता होता है, तब ज्ञान केवल धारणा की बुनियाद को समझने का माध्यम नहीं बन जाता है।

श्री श्री आनंदमुनि



कोई व्यक्ति चाहे किना भी काबिल तयों न हो, वह अकेले नहीं रह सकता। हम उस समुदाय पर निर्भर होते हैं, जिसमें हम रहते हैं। दूसरों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करके, हम असल में अपना ही मला कर रहे हैं।

अनुलोम-विलोम संवेदनशीलता



डिजिटल सुविधा ने दूरी का दर्द कम किया

मोबाइल ने आधुनिक जीवन की व्यस्तता, जिम्मेदारियों के दबाव और दूर रहने की मजबूरी के इस दौर में हमारे जीवन को अनुकूल बनाया है, हालांकि समय काम कर दिया है। एक तरह, हम साथ रहकर भी दूर-दूर हैं, तो इसका दुष्प्रभाव फलतः यह है कि हम दूर रहकर भी साथ होने का एहसास कर सकते हैं। मोबाइल पर हालचाल फूल लेना, वीडियो कॉल पर चेहरा देख लेना और सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं देना रिश्तों की गमाईती को बरकरार रखता है। इसके कारण लोग अपनी व्यस्त जिंदगी में से थोड़ा सा समय निकालकर अपनी से बातचीत कर लेते हैं।

मोबाइल और इंटरनेट के आने से पहले लोग अपने परिजनों और मित्रजनों से वार्ड में बार मिल पाते थे। उनका हाथ-आपुनिक सुविधा के आने से अब इसे संभव कर दिया है। अब लोग और व्यस्तता और दूरी की वजह से कम से कम अपने

परिजनों को ऑनियन विदाई ऑनलाइन ही देखकर देख सकते हैं, उनके अंतिम तो मनन कर ही सकते हैं।

यार कौन, कोरना महामारी के दौर को, जब देश में और आसपास देशों के वायरल लोग अपनी ऑनियन दर्द की स्थिति में भी नहीं रह पाते, क्योंकि व्यवहार के संकेतक के मध्य के साथ-साथ आधुनिकता का कोई साधन नहीं था। ऐसे में, वह मोबाइल ने हमारे जीवन में एक नई छवि प्रदान की। हमारे जीवन को संतुलित दिया और विस्तृत पता होने का एहसास कराया।

समिति में विश्वास में रहने वाले परिजनों की सुविधा के लिए ऑनियन संस्कार के कारण आमरण की सुविधा शुरू की है। इससे दूर बैठे लोगों को वीडियो कॉल या लाइव स्ट्रीम के जरिए अपने परिवार के ऑनियन दर्द की सुविधा मिल गई है।

मुकेश प्रसाद ठाकुर, अधिवक्ता

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

Lifetime Free Newspapers Access

Editorials PDF

- English Editorials PDF with International Newspapers Editorials [35-40 pages]
- Hindi Editorials PDF
- Daily Vocabulary PDF

Magazine Channel

National & International
[General & Exam related]

International Newspapers

Newspapers around world.
Asian, European & American

Hindi Newspapers

- 1) दैनिक जागरण
- 2) जनसत्ता
- 3) हरिभूमि
- 4) हिंदुस्तान

Indian Newspapers Channel

1. The Indian Express

2. The Hindu

3. Business Line

4. Financial Express

5. Times of India

6. Hindustan Times

7. Economic Times

8. Live Mint

9. Business Standard

